भारतसरकार
पंचायतीराजमंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं-1204
दिनांक03.12.2024कोउत्तरार्थ

पंचायती राज के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण

1204. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज के प्रतिनिधियों को प्रबंधन नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के साथ सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का ब्यौरा क्या है और उनके क्या उ द्देश्य हैं,

(ग) प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है और हिमाचल प्रदेश में जिला-वार कितने पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है, और

(घ) हिमाचल प्रदेश राज्य में पंचायतों को वर्तमान में प्रदान की जा रही इंटरनेट और कम्प्यूटर जैसी अवसंरचना का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो. एसपी. सिंहबघेल)

(क) और (ख) जी हाँ, महोदय। केंद्रीय प्रायोजित योजना "रिवैम्प्ड राश्त्रीय ग्राम स्वराज अभियान" का उद्देश्य पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की लगातार क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर शासन क्षमता का विकास करना है।

नेतृत्व प्रशिक्षण के दायरे को और विस्तारित करने के लिए, मंत्रालय ने एक नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) तैयार किया है, जो पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नेतृत्व क्षमता को सशक्त बनाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर समुदाय के नेताओं के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए एक रूपांतरकउपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

मंत्रालय ने नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 6 IIMs(अहमदाबाद, शिलॉन्ग,

अमृतसर, जम्मू, बोधगया, रोहतक), IIT धनबाद, और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (IRMA) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) अब तक, देश भर के 193 प्रतिभागियों, जिनमें 38 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि शामिल हैं, को चार आईआईएम और आईआरएमए में आयोजित पांच प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (एमडीपी) के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।हिमाचल प्रदेश राज्य से प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले पंचायती राज प्रतिनिधियों का जिला-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय द्वारा RGSA योजना के तहत सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायतों के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों के पास कंप्यूटर हैं, इसलिए योजना के तहत कोई भी कंप्यूटर मंजूर नहीं किया गया है।

भारतनेट परियोजना को दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि देश भर की सभी ग्राम पंचायतों और उनके समकक्ष संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। हिमाचल प्रदेश में सेवा-तैयार ग्राम पंचायतों की जिला-वार स्थिति अनुबंध-II में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1204 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आईआईएम में प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले पंचायती राज प्रतिनिधियों का जिला-वार विवरण

संस्थान	पद	जिला
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	अध्यक्ष, जिला परिषद	चंबा
भारतीय प्रबंधन संस्थान,अमृतसर	अध्यक्ष, जिला परिषद	कुल्लू
	जिला परिषदकाएक सदस्य	शिमला

अनुबंध-II

दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1204 के भाग (घ)के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

हिमाचल प्रदेश राज्य में जिलेवार सेवा-तैयार ग्राम पंचायतें"

क्र सं.	जिला	सेवा तैयारग्रामपंचायतें
1	बिलासपुर	0
2	चंबा	45
3	हमीरपुर	176
4	कांगड़ा	0
5	किन्नौर	65
6	कुल्लू	0
7	लाहौलऔरस्पीति	41
8	मंडी	26
9	शिमला	6
10	सिरमौर	1
11	सोलन	56
12	ऊना	0